

प्रेषक,

विनोद फोनिगा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन-2

रोहरादून दिनांक: 11/05/2009

विषय- वित्तीय वर्ष 2009-10 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (एसओसीएसपीओ) में आयोजनागत पक्ष की राज्य योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1587-88/लेखा-प्रस्ताव आयोएससीएसपी/2009-10, दिनांक 10-09-2009 के संदर्भ में एवं प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या-515/XV/11/2009, दिनांक 28-07-2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जाति के कन्यागार्थ डेरी विकास विभाग को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न मुदों में कुल धनराशि रु० 60-10 लाख (रु० साठ लाख दस हजार मात्र) आपके निर्वहन पर रखते हुये इस आहरण कर व्यय करने की भी राज्यपाल महोदय सहित वित्तीय स्वीकृति प्रदान करा है-

(धनराशि आठ रु० में)

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि
1.	सिविल कार्य	24.79
2.	प्लाण्ट नशीनरीज	0.91
3.	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विपणन नेटवर्क	10.18
4.	यातायात एवं प्रकृषकीय अनुदान	24.22
योग-		60.10

उपरोक्त के अतिरिक्त क्रमांक-01 एवं 02 पर अंकित मदों की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

- 1- इस संकेत में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में भूमाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय रकम ही इस धनराशि का एक मुश्ता आहरण न किया जाय।
- 2- सभी कार्यक्रमों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्य का निर्धारण भी आपके द्वारा तयकर कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सुचारु उपलब्ध करा दी जाय।
- 3- खर्च का भूगर्भीय सर्वेक्षण करा लिया जाय।
- 4- उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान वित्तव्ययता संबंधी आदेशों व विनियम हस्त मुद्राका में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम 75% से अधिक पूर्व प्रावधानों के दिशे किया जाय।
- 6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2010 तक उपयोग कर प्रमाणिक शासन का संपत्तक कराया जाय।

C

- 7- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्रतिष्ठित व्यय की परतूरी की जायेगी।
- 8- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन व्यय की सूचना कोषागार द्वारा प्रमाणित करवाकर सचवा एवं विभांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 9- स्वीकृति की जा रही धनराशि के सादेस कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेंसी द्वारा करवाया जायेगा। साथ ही राशि का तत्काल आहरण कर संबंधित जनपदीय पुंख संघों को उपलब्ध कराया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय बाबू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान सचवा-30 के अर्वागत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-अद्योजनगत-102-डेरी विकास परियोजनागत-02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पेन्सन्ट प्लान-0201-डेरी विकास योजना-20-सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सचवा-23/वि0अनु0-4/2009, दिनांक 13 फेब्रवर 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-सचोपरी

महर्षि

(विमोद कोनिया)
सचिव।

संख्या-1655 (1)/XV-2/1(08)08-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, आदराय मॉर्टन थिथिंग, सहायपुर रोड, देहरादून।
- 2- मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं पीडी गढ़वाल।
- 3- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर-अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं परम्प विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- वित्त अनुभाग-04/नियोजन अनुभाग/समाज कल्याण प्रकोष्ठ।
- 6- चरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- माई फाइल।

अज्ञा के
21/11/08
(जी0बी0 ओसी)
सचिव।